

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

क्र. आर.ई.जी. (आई.टी.) 4240

दिनांक:-13.06.2016

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग,
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

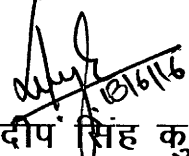
विषय :- "ईज ऑफ ड्रुइंग बिजनेस"—भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्टेट बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान-2016 कार्य बिंदुओं के क्रियान्वयन की प्रगति एवं समीक्षा।

संदर्भ :- विधि विभाग का पत्र क्र. 1375/21-ब(एक)/2016 भोपाल दिनांक 07.04.2016, पत्र क्रं. 1609 दिनांक 27.04.2016 एवं स्मरण पत्र क्रं. 1703 दिनांक 04.05.2016

-----00-----

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भित पत्रों के बिंदु क्रं.-330 के संबंध में लेख है कि दिनांक 01.05.2016 की स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की संख्या 1261 रही है। जबकि कुल रिक्त पदों की संख्या 200 है।

इस प्रकार दिनांक 01.05.2016 की स्थिति में न्यायिक अधिकारियों के 86.31% प्रतिशत पद भरे हुए हैं। इसके अतिरिक्त, 100 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं 96 सिविल जज वर्ग - 2 के नये पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।


(कुलदीप सिंह कुशवाह)
रजिस्ट्रार (आई.टी)